

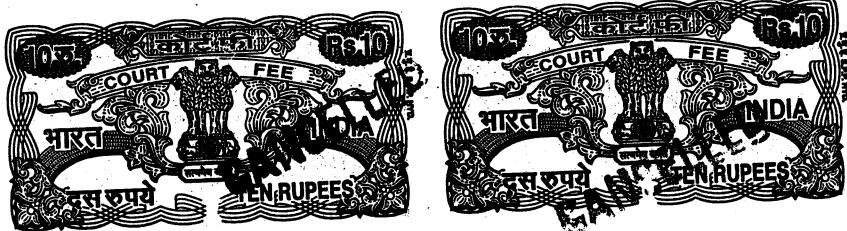
न्यायालयके ब्रॉमारु राज्यपाल, गवाँत्तियर मध्य प्रदेश।

R-19  
17-10-12

3077

क्रमांक  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 17-10-12 को प्राप्त  
नं।

क्रमांक  
दिनांक 17-10-12 को  
न्यायालय अधिकारी नं प्र. अधिकारी



R. 3592-II/12

देववती पुरी सीताराम ब्राह्मण,

निवासी ग्राम विघारपुर, तहसील कौतमा,

जिला अनूपपुर ₹५० प्र० = ----- आवैदिका

// बनाम //

अनावैदिक.

मध्य प्रदेश शासन --

निगरानी, घिरहू निर्धन न्यायालय तहसीलदार  
कौतमा, जिला अनूपपुर म०प्र०, ₹१०७० प्र० 26/अ-12,  
20.10.2011, आवैदिका दिनांक 20/07/2011

निगरानी, अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० ₹१०८० 1959

मान्यवर,

आवैदिका, नि मालिखित कारपौ से, निगरानी प्रस्तुत कर,

निवैदन करती है :-

1- यह कि, अधीनस्त न्यायालय का आदेश कानून सवै वाकायत  
गलत है।

2- यह कि, अधीनस्त न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौरव नहीं किया  
कि, आवैदिका ने, अपने पद के लिए स्थानित्य तथा कठीन दखल की आर  
का ग्राम लामा टोला, तहसील कौतमा, जिला - अनूपपुर म०प्र० आरा जो ग्रा  
म क्रमांक 33/8, रक्षा 0-809६०, 69/2 रक्षा 0-263६०, 77/1 रक्षा  
0-243६०, 86/1 रक्षा 0-283६०, 87/1 रक्षा 0-125६०, 695/

रक्षा 0-231६०, कुल किता 6, के बटकिन किये जाने हेतु आवैदन पर  
अधीनस्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जी।

//2//

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

देववती / शासन

प्रकरण क्रमांक निरो 3592-दो / 12

जिला - अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/4/16	<p>आवेदिका द्वारा यह निगरानी तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 26/अ-12/2010-11 आदेश दिनांक 20-07-2011 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।</p> <p>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि का बटांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को नक्शा तरमीम करने का आदेश दिया, जिसमें खसरा नं 0 33/8 में जहां आवेदिका का कब्जा था, वहां खसरा नं 0 33/1 (क) दिया जबकि खसरा नं 0 33/1 (क) की तरमीम हेतु कोई आवेदन पत्र आवेदक ने तहसीलदार को नहीं दिया था। आवेदिका ने 33/8 रकवा 0.809 है 0 का बटा नं 0 कायमी हेतु आदेश जारी करने का निवेदन किया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया तथा आवेदिका अभिभाषक के तर्क सुने। आवेदिका के द्वारा आवेदन में बटांकन तथा नक्शा तरमीम त्रुटिपूर्ण करने के आदेश के विरुद्ध निगरानी की है। जबकि उसके द्वारा तहसीलदार कोतमा के आदेश दिनांक 20-07-2011 के आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। जिसका आवेदिका द्वारा दिनांक 21-05-2010 को सीमांकन हेतु प्रस्तुत किये गये, आवेदन पर सीमांकन पश्चात् सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा सीमांकन की पुष्टि की है। जबकि निगरानी आवेदन में</p>	(1)

सीमांकन की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होने के विरुद्ध कोई उल्लेख नहीं किया है। यदि आवेदिका तहसीलदार द्वारा किए गए नक्शा तरभीम के आदेश से असन्तुष्ट थीं, तो उसके विरुद्ध सक्षमधिकारी के समक्ष अपील आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। अतः उक्त स्थिति में निगरानी ग्राहय करने को कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी अग्राहय की जाती है।

सदस्य